(च) तथा (छ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सैनिक फार्म में 1990 से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पी.सं० 86–ए के बारे में सुरजीत सिंह बनाम दिल्ली नगर निगम के एक मामले में स्थगन आदेश दिया हुआ है। यह मामला न्यायालय में चल रहा है ।

Flood prone areas ia tlie State of Bihar

637. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: WiH the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) which are the flood prone areas in the State of Bihar.

(b) out of these areas, which areas suffered from floods during the last three years;

(c) the estimates of damage done due to floods submitted by Bihar Government luring the last three years;

(d) the amount of aid provided by the Central Government against those estimates during the last three years, and

(e) the reasons of ihe differences, if anjy^ between the estimates submitted by the Bihar Government and the Centra) assistance provided for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) Rashtriya Baih Ayog lias assessed an area of 42.6 Iakh hectare a_s flood prone in the State of Bihar. On an average an area of about 14.45 lakh hectare gets affected aiuiually. During the last three years 14 districts were mainly affected due to $flood_s$ viz., Darbhanga, Gopalganj, Khagaria, Bhagalpur, Madhubani, MuzafEarpur, Madhepura, Patna, Saharsha, Supaul, Sitamarhi, Samastipur, West Chaparan and Katihar,

(c) to (e) Government of Bihar has reported damage to crops, houses and public utilities to the extent of Rs. 20.14 crores, Rs. 22.14 lakhs and Rs. 306.41 crores during 1991-92, 1992-93 and 1993-94 respectively. Under the existing scheme of financing relief expenditure, tha State Government undertakes relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities including floods using the corpus of the calamity Relief Fund (CRF). Bihar has an annual CRF of Rs. 35.00 crores consisting of Central share of Rs. 26.25 crore and State share of Rs. 8.75 crore. The Central share of CRF has been released to the Staie Government during the last 3 years for under-taking relief and rehabiltation measures in $_w$ako of natural calamities.

सरदार सरोवर परियोजना पर पुनर्विचार करने से संबंधित प्रतिवेदन की जांच

638. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने सरदार सरोवर परियोजना पर पुनर्विचार करने के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन की जांच करने के लिए सरकार को निदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा समिति के प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थूगन) (क) से (घ) जी, हां। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार की अनुक्रियायें सुनवाई की अगली तारीख अर्थात् 13–12–94 को न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए । तथापि, इस रिपोर्ट की गोपनीयता को बनाए रखा जायेगा ।

उड़ीसा में पोलेरु सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाना

639. **श्री भगवान माझी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिग्रहण समस्या और अन्य अवरोधों को, जिनसे उड़ीसा में पोलेरु